आयोग की जांच हो रही है, उचित फोरम पर रखें बात: हाईकोर्ट

संभल हिंसा की एसआईटी से जांच की मांग खारिज

अदालत से

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में हिंसा, आगजनी और फायरिंग की जांच हाईकोर्ट के रिटायर जज की देखरेख में एसआईटी से कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने याचिका वापस लेने के आधार पर दिया।

बुधवार को सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को जानकारी दी कि सरकार ने प्रकरण की जांच के लिए हाईकोर्ट जज का न्यायिक आयोग गठित करने का आदेश दे दिया है। इसके बाद याची की ओर से पुलिस के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग पर बल दिया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि आयोग की जांच हो रही है। याची चाहे तो उचित फोरम पर बात रख सकता है। इस पर याची के अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने की प्रार्थना की जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

वाराणसी के सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार डॉ आनंद प्रकाश तिवारी जनहित याचिका में हाईकोर्ट के रिटायर जज के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने की मांग की थी।

दो अन्य पीआईएल पर आज सुनवाई: गुरुवार को संभल हिंसा से जुड़ी दो अन्य जनहित याचिकाओं पर सुनवाई होने की संभावना है। एक में घटना में मारे गए और गिरफ्तार लोगों की सूची जारी करने आदि की मांग है। दूसरी में हिंसा के लिए संभल के डीएम और एसपी के खिलाफ एफआईआर कर उनकी गिरफ्तारी की मांग है।

संभल में बुधवार को हिसां प्रभावित क्षेत्र में पुलिस का सख्त पहरा रहा।

दंगा मुक्त यूपी सपा-कांग्रेस को हजम नहीं : केशव मौर्य

लखनऊ। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को राहुल गांधी द्वारा संभल जाने के प्रयास पर करारा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर कहा कि दंगा मुक्त प्रदेश सपा और कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा। यूपी में सरकार ने दंगा मुक्त प्रदेश का सपना साकार किया है, जो सपा-कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा।

वोटों के लिए संभल जाना चाहते हैं राहुल : ब्रजेश

लखनऊ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि राहुल गांधी वोटों की फसल काटने के लिए संभल जाना चाहते हैं। अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दोनों ही नेताओं को प्रदेश के अमन-चैन से कोई लेना-देना नहीं है। वे सिर्फ अपनी राजनीति चमकाकर कानून-व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। जनता भी उनका असली आचरण जानती है।

पोल न खुले इसलिए भाजपा ने हिंसा कराई: अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि विधानसभा उपचुनाव में धांधली की पोल न खुल जाए इसलिए भाजपा ने संभल में हिंसा कराई। भाजपा की ये सत्ता भूख की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि 19 नवंबर को भाजपा ने संभल में सर्वे कराकर माहौल खराब करने का प्रयास किया, जब उस दिन सब कुछ शांत रहा तो फिर षड्यंत्र के तहत दोबारा सर्वे की योजना बनाई। किसी भी दल के नेता को संभल नहीं जाने दे रही है।

प्रियंका गांधी की शाह से मुलाकात

नई दिल्ली, विसं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए मदद मांगी। इस दौरान केरल से कांग्रेस, आईयूएमए और आरएसपी के सांसद भी मौजूद थे।

मुलाकात के बाद संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमने केंद्रीय गृहमंत्री को वायनाड की स्थिति से अवगत कराया। उन्हें कहा कि वायनाड में भूस्खलन से लोग तबाह हो गए हैं। लोगों को त्वरित सहायता की जरूरत है। केंद्र से वायनाड के लोगों को उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम सभी सांसदों ने गृहमंत्री से राजनीति से ऊपर उठकर वायनाड के लोगों की मदद की अपील की है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीड़ितों से मिले थे, तब लोगों को मदद की उम्मीद जगी थी। पर अभी तक कोई सहायता नहीं मिल पाई है। केरल के सांसदों ने गृहमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा है।

गिरफ्तार किसान रिहा आज फिर महापंचायत

किसानों का विरोध

ग्रेटर नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट पर बुधवार को करीब आठ घंटे तक चली किसानों की महापंचायत के बाद देर शाम पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किए गए सभी 123 किसानों को रिहा कर दिया। जेल से रिहा होने के बाद किसान जीरो प्वाइंट पर चल रही महापंचायत में पहुंचे। अब गुरुवार को होने वाली महापंचायत में आगे की रणनीति घोषित होगी।

संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसानों ने सुबह 10 बजे महापंचायत शुरू की। इसमें गौतमबुद्ध नगर के अलावा गाजियाबाद, मेरठ समेत पश्चिमी यूपी से हजारों महिला और पुरुष किसान हिस्सा लेने पहुंचे। महापंचायत की अध्यक्षता श्यामी प्रधान और संचालन भाकियू नेता राजीव मलिक ने किया। महापंचायत में राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत ने हिस्सा लिया। गौरव ने कहा कि मांगें पूरी न होने तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे।

महापंचायत में शामिल होने के लिए सुबह नौ बजे से ही किसान ग्रेटर नोएडा पहुंचने शुरू हो गए थे। 11 बजे तक पंडाल किसानों से खचाखच भर गया। महापंचायत शाम छह बजे तक चली, जिसमें किसानों ने 10 प्रतिशत आबादी भूखंड, बढ़ा हुआ 64.7 प्रतिशत मुआवजे और दलित प्रेरणा स्थल से गिरफ्तार 123 किसानों की रिहाई की मांग की। साढ़े चार बजे तक सभी किसानों को जेल से रिहा कर दिया गया।

राकेश टिकैत को नहीं जाने दिया नोएडा : अलीगढ़/नोएडा। आंदोलन में शामिल होने जा रहे भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को बुधवार सुबह टप्पल में यमुना एक्सप्रेसवे पर रोक लिया गया। काफी देर बहस के बाद उन्हें थाने ले आया गया।

संभल को लेकर सियासत गरमाई

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने को लेकर बुधवार को सियासी घमासान छिड़ गया। कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा तो दूसरी ओर भाजपा भी हमलावर रही।

संविधान की धज्जियां उड़ाईं: खरगे

आमने-सामने

नई दिल्ली, एजेंस। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा। खरगे ने कहा कि राहुल को संभल हिंसा के पीड़ितों से मिलने की अनुमति नहीं देकर वे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

खरगे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राहुल को रोकना इसी बात को साबित करता है कि भाजपा-आरएसएस अपने विभाजनकारी एजेंडे में व्यस्त हैं। दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करना ही भाजपा-आरएसएस की विचारधारा है। उसके लिए उन्होंने न केवल संविधान से पारित उपासना स्थल कानून को तार-तार किया, पर अब वो अपने नफरत के बाजार की शाखाओं को हर जगह खोलने पर उतारू हैं।

राहुल का दौरा मजबूरी: भाजपा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। राहुल गांधी के संभल जाने के प्रयास पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को कहा कि यह कांग्रेस नेता की लाचारी और सपा से उनकी प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। ऐसा उन्होंने सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए किया।

भाजपा नेता ने कहा कि राहुल का संभल दौरे का प्रयास मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक औपचारिकता मात्र थी, क्योंकि वह इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने में विफल रहे हैं। यह प्रयास कांग्रेस और सपा के बीच अपने मूल वोट बैंक को वापस पाने की प्रतिस्पर्धा से प्रेरित था, न कि कांग्रेस इस मुद्दे से सहानुभूति रखती है।

देश 30s

पश्चिम बंगाल के साथ कोई भेदभाव नहीं

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में दो साल से अधिक समय से मनरेगा के तहत मिलने वाली राशि रोके जाने के सवाल पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि बंगाल के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। हम पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों के बारे में भी चिंतित हैं। हमने कुछ अनुपालनों के लिए कहा है। यदि राज्य उन्हें पूरा करता है, तो हम इस पर विचार करेंगे।

'भूमि अधिग्रहण के लिए जरूरी हो तो धरना दें'

नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद शशि थरूर से कहा कि वह केरल में एक रेल परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के मकसद से धरने पर बैठ सकते हैं। थरूर के निर्वाचन क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में नेमोम रेलवे टर्मिनल परियोजना पर एक सवाल का जवाब देते हुए वैष्णव की टिप्पणी आई।

कनाडा और चीन पर समिति को जानकारी दी

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को चीन और कनाडा से जुड़े मुद्दों पर एक संसदीय समिति को जानकारी दी। बताया कि भारत के साथ कनाडा के संबंधों में गिरावट के लिए वहां की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने विदेश मामलों की स्थायी समिति को बताया कि लद्दाख में चीन के साथ सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।

हेमंत के मंत्रियों को आज गवर्नर दिलाएंगे शपथ

रांची। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट का विस्तार गुरुवार को होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सबसे पहले स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद झामुमो, कांग्रेस और राजद कोटे के 10 से 11 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। झामुमो कोटे से पांच या छह मंत्री, कांग्रेस से चार और राजद से एक विधायक मंत्री बनेंगे।

शशि थरूर को भाया बंदर का 'अपनापन'

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नई दिल्ली में अपने आवास पर बुधवार को एक बंदर के साथ कुछ ऐसा 'असाधारण अनुभव' हुआ कि वो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। थरूर ने इससे जुड़ी तस्वीरें 'एक्स' पर साझा कीं और लिखा,' आज एक असाधारण अनुभव हुआ। सुबह जब मैं बगीचे में बैठा समाचारपत्र पढ़ रहा था, एक बंदर मेरे पास आया और गोद में बैठ गया। उसे मैंने दो केले दिए जो उसने खा लिए। उसने मुझे गले लगाया और अपना सिर मेरी छाती पर रख दिया और झपकी ली।'

छह केंद्रीय विवि ने प्रवेश नीति बदली

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कहा कि छह केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने साल में दो बार प्रवेश देने की नीति अपनाई है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी साझा की। मजूमदार ने कहा, यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को साल में दो बार जुलाई या अगस्त और जनवरी या फरवरी में छात्रों को प्रवेश देने की नीति को मंजूरी दे दी है। हालांकि, साल में दो बार छात्रों को दाखिला देना उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए वैकल्पिक है, जो द्विवार्षिक प्रवेश को संभालने के लिए उनकी तैयारियों पर निर्भर करता है।'

सिंधिया मराठी में बोले-बीएसएनएल मुनाफे में

नई दिल्ली। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बुधवार को अलग अंदाज नजर आया। महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद श्रीमती प्रतिभा सुरेश धानोरकर के मराठी में बीएसएनएल के बारे में पूछे गए प्रश्न का उन्होंने मराठी में जवाब दिया। इस दौरान शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत से साथ उनकी मराठी नोकझोंक भी हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बीएसएनएल अब मुनाफे में है। यूपीए सरकार के वक्त नौ हजार करोड़ रुपये के घाटे में चल रही बीएसएनएल अब दो हजार करोड़ रुपये के मुनाफे में है।

निसार का प्रक्षेपण मार्च में हो सकता है

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि इसरो-नासा संयुक्त उपग्रह के अगले साल मार्च में लॉन्च होने की संभावना है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, सिंह ने कहा कि नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार को इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया जाना था, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने पाया कि इसके 12-मीटर रिफ्लेक्टर एंटीना में कुछ सुधार की जरूरत है, जिसके बाद इसमें देरी हो गई। इसके सुधार के लिए अमेरिका ले जाना पड़ा। कहा कि रडार एंटीना रिफ्लेक्टर को उपग्रह के साथ पुन: एकीकरण के लिएअक्तूबर में भारत वापस भेज दिया गया था।

स्मार्ट शहरों की तर्ज पर स्मार्ट गांव बनें : गडकरी

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को स्मार्ट शहरों की तर्ज पर स्मार्ट गांव बनाने की वकालत की। गडकरी स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के 42वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। गडकरी ने कहा, हम स्मार्ट शहर बना रहे हैं। हम इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं कि हमें स्मार्ट गांव कैसे बनाने चाहिए। उन्होंने कहा, यह बात मेरे दिमाग में है। मैं भी एक स्मार्ट गांव बना रहा हूं।

बॉयलर विधेयक 2024 को राज्यसभा की मंजूरी

नई दिल्ली। बॉयलर विधेयक 2024 को बुधवार को राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। यह सौ साल पुराने बॉयलर कानून की जगह लेगा। इसका मकसद बॉयलर का विनियमन, भाप-बॉयलर विस्फोट से लोगों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना, देश में इसके विनिर्माण, स्थापना और उपयोग के दौरान पंजीकरण और निरीक्षण में एकरूपता लाना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि श्रमिकों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है।

संसद सत्र

सरकार से किसानों को लेकर तीन प्रमुख मांगें

तीन मांगों में पहली एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। दूसरी, इसकी गणना व्यापक उत्पादन लागत के आधार पर 1.5 से गुणा करके की जानी चाहिए और तीसरी अगर 16 लाख करोड़ के कॉर्पोरेट ऋण माफ किए जा सकते हैं, तो 2-3 लाख रुपये के कृषि ऋण माफ क्यों नहीं किए जा सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बुधवार को लोकसभा में अदाणी मामले पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव नोटिस में अदाणी समूह के खिलाफ गंभीर आरोपों के बावजूद सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की चुप्पी पर तत्काल चर्चा की मांग की गई।

राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट

गतिरोध

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर हंगामे के बाद विपक्षी सदस्यों ने बुधवार को सदन से वॉकआउट किया। विपक्षी सदस्यों ने सदन में सरकार को किसान विरोधी बताते हुए नारेबाजी की। एक दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री से पूछे गए तीखे सवालों को विपक्ष ने अपना हथियार बनाया। हालांकि, उपराष्ट्रपति ने विपक्ष से कहा कि वे इस मसले पर राजनीति न करें। सदन से वॉकआउट के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्री से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने एमएसपी की बात की। उन्होंने नवंबर 2021 में तीन काले कृषि कानूनों को वापस लेने के समय मोदी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न वादों की बात की। कहा कि कांग्रेस हमेशा से तीन बड़ी मांगें करती रही है।

इंडिया गठबंधन के सांसदों ने अदाणी समूह से जुड़े मुद्दे को लेकर बुधवार को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। ● एएनआई

ओम बिरला बोले-संसद का प्रवेश द्वार अवरुद्ध न करें

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को सदस्यों से संसद का प्रवेश द्वार अवरुद्ध न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वह पहले भी इस तरह का आग्रह कर चुके हैं। कई महिला सदस्यों ने प्रवेश द्वार पर अवरोध की शिकायत की है। इसलिए, सभी दलों से अपील है कि सदस्यों के संसद भवन आने के वक्त प्रवेश द्वार पर रुकावट पैदा न करें। दरअसल, अदाणी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के कई घटकदलों ने बुधवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया था। विपक्षी पार्टियों ने अदाणी मामले में जेपीसी के गठन की मांग की है। लोकसभा अध्यक्ष सदन में जिस वक्त राजनीतिक दलों को यह नसीहत कर रहे थे, उसी वक्त कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने सवाल किया कि प्रदर्शन कहां पर करें।

मंत्री उनका जवाब न दें, जिन्हें बोलने की अनुमति न हो

ओम बिरला ने केंद्र के मंत्रियों से कहा कि वे उन सदस्यों की बातों का जवाब देने की आदत छोड़ दें, जिन्हें बोलने की अनुमति आसन से नहीं मिली है। उन्होंने यह टिप्पणी उस वक्त की, जब लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से जुड़े पूरक प्रश्न पूछे जा रहे थे। प्रह्लाद जोशी के उत्तर देते समय सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुछ टिप्पणी की।

UPSIDA UTTAR PRADESH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
UPSIDA Complex, A-1/4, Lakhanpur, Kanpur-208024, Uttar Pradesh, India

NOTICE INVITING GeM Portal

UPSIDA invites online Bids from eligible Bidders working in any central/state department or government/semi government/PSU undertakings for the works as below-

Name and Description of work	Date of availability of Bid documents online	Last date to fill/ upload the Bid through GeM Portal
Empanelment of Urban Designers/ Landscape Architects/ Lighting designers/ Structural & Hydraulic Drain Designer/ solid waste management consultant for upcoming projects of UPSIDA	06.12.2024 at 11:00 AM	27.12.2024 at 5:00 PM

- The Bid document shall be available online at **GeM Portal** from **06.12.2024** at 11.00 AM to **27.12.2024** at 05.00 PM.
- Pre bid Meeting shall be **13.12.2024** at **11.00 AM** Link will be made available separately.
- Opening of Technical Bid shall be **27.12.2024** at **5.30 PM.**
- For submission & other tender details, please refer detailed Bid document available on websites **GeM Portal.** Other details are also available on UPSIDA website www.onlineupsida.com and Corrigendum/amendments etc, if any, will be notified on these websites only and separate advertisement will not be made for the same.

UPSIDA reserves the right to accept or reject any application without assigning any reason or incurring any liability whatsoever.

Uttar Pradesh State Industrial Development Authority

कानपुर विकास प्राधिकरण

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित परेड स्थित (क्रिस्टल) मल्टीलेविल पार्किंग के संचालन हेतु ई-नीलामी की सूचना

कृपया कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित परेड स्थित (क्रिस्टल) मल्टीलेबिल पार्किंग के संचालन हेतु नीलामी ई-ऑक्शन के माध्यम से की जानी है. इस हेतु आवेदकों को प्राधिकरण के बेवसाइड www.kdaindia.co.in पर उपलब्ध ई-ऑक्शन के लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराने के उपरान्त निर्धारित पजीकृत धनराशि जमा करने के पश्चात आवेदक घर से अथवा कहीं से भी कम्प्यूटर अथवा मोबाइल से बोली लगा सकता है। प्राधिकरण द्वारा आवेदकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये Kanpur Development Authority के नाम की मोबाइल ऐप भी तैयार की गयी है। जिसको आवेदक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर इसके माध्यम से भी ई-ऑक्शन में प्रतिभाग कर सकते है।

नीलामी/बिडिंग प्रारम्भ दिनांक व समय :- 06/12/2024 प्रातः 11:00 बजे से
नीलामी/बिडिंग अनिम दिनांक व समय :-20/12/2024 सायं: 05:00 बजे स
नीलामी/बिडिंग घोषित दिनांक व समय :- 21/12/2024 आपरान्ह: 01:00 बजे से

कुल पार्किंग संख्या	पार्किंग समय	दरें प्रतिदिन एक वर्ष के लिये
चार पहिया वाहन 292	0 से 4 घण्टा तक 4 से 8 घण्टा तक 8 से 24 घण्टे तक	रू0 20 प्रति वाहन रू0 30 प्रति वाहन रू0 50 प्रति वाहन
दो पहिया वाहन 133	0 से 4 घण्टा तक 4 से 8 घण्टा तक 8 से 24 घण्टे तक	रू0 10 प्रति वाहन रू0 15 प्रति वाहन रू0 25 प्रति वाहन

नीलामी की नियम व शर्तें:- 1- ई-ऑक्शन की मुख्य शर्तें कानपुर विकास प्राधिकरण की बेवसाइट पर उपलब्ध है। 2- ई-ऑक्शन की स्वीकृति/अस्वीकृति का सम्पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा।

(केयर टेकर) (प्रभारी मुख्य अभियन्ता)

'भारत-चीन रिश्ते समझौते पर निर्भर'

राज्यसभा

नई दिल्ली, विसं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को राज्यसभा में भारत और चीन के रिश्तों को लेकर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने भारत-चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। साथ ही कहा कि दोनों देशों के संबंध एलएसी की मर्यादा का सख्ती से सम्मान करने और समझौतों का पालन करने पर निर्भर होंगे।

जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ एलएसी पर कुछ हिस्से को लेकर असहमति है, जिसे दूर करने के लिए दोनों देश समय-समय पर बातचीत करते हैं। कहा कि गलवां घाटी में जून 2020 में हुई झड़प की घटना का भारत-चीन के रिश्तों पर असर पड़ा था। यह 45 वर्षों में पहली बार सीमा पर सैनिकों की जान जाने का मसला नहीं था, बल्कि इसके चलते एलएसी के दोनों तरफ भारी मात्रा में हथियारों की तैनाती हुई थी। उन्होंने कहा कि इस बीच तमाम चुनौतियों के बावजूद, हमारे सैन्य बलों ने कोविड काल, रसद और भीषण ठंड का सामना करते हुए गलवां घटनाक्रम में समुचित प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री ने कहा कि चरण-दर-चरण प्रक्रिया के माध्यम से पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी का काम संपन्न हो गया है, जो अभी देपसांग और डेमचोक में पूरी तरह संपन्न होना है। हाल की घटनाओं से हम प्रभावित हुए हैं। हम स्पष्ट हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना हमारे संबंधों के विकास की बुनियादी शर्त है।

हमारा आचरण संस्था को कमजोर कर रहा : धनखड़

स्पष्टीकरण को लेकर सभापति धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों के आचरण पर निराशा व्यक्त की। कहा, मैंने बार-बार सदस्यों का ध्यान इस तथ्य की ओर किया है कि हम पर पूरे देश की नजर है। हमारा आचरण संस्था को गंभीर रूप से कमजोर कर रहा है। जब मैं हर बार देखे गए अभद्र व्यवहार और परिलक्षित होने वाली शारीरिक भाषा का उल्लेख करता हूं, तो इससे मुझे कोई प्रशंसा नहीं मिलती। लेकिन मैं यह केवल सदस्यों की गरिमा को बहाल करने के लिए करता हूं।

'हर ट्रेन टिकट पर 46% सब्सिडी'

नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार हर रेल यात्री को टिकट पर औसतन 46 फीसदी सब्सिडी दे रही है। रेल मंत्रालय यात्रियों के लिए सब्सिडी पर हर साल 56 हजार 993 करोड़ रुपये सब्सिडी पर खर्च करता है। यात्रियों से हर सौ रुपये की यात्रा सेवा की कीमत में सिर्फ 54 रुपये लिए जाते हैं। रेल यात्रियों को टिकट पर 46 फीसदी सब्सिडी दी जाती है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान वरिष्ठ नागरिकों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ियों को सब्सिडी के बारे में सवाल किए जाने पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार यात्रियों को कुल 56,993 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है।

ग्रामीण विकास पर ₹ 1.03 लाख करोड़ खर्च: शिवराज

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ग्रामीण विकास मंत्रालय की उपलब्धियों का ब्योरा दिया। इसमें उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। चौहान ने बताया कि इस साल मंत्रालय का बजट एक लाख 84 हजार करोड़ था उसमें से एक लाख 3 हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि गांवों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। ग्रामीणों के रोजगार पर सरकार काम कर रही है। गरीबों को घर दिए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा पूछे गए सवालों और किसान आंदोलन को लेकर कोई बात नहीं की। शिवराज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 2 करोड़ नए घर अगले पांच साल में 3.06 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से बनाए जाएंगे। कोई भी पात्र वंचित न रहे इसके वर्तमान में 13 एक्सक्लूशन क्राइटेरिया को संशोधित कर 10 कर दिया गया है।

पहल | 'देववन' बन जाने के बाद इनमें लोग लकड़ी काटने और अन्य वन उत्पाद निकालने नहीं जाते

देवभूमि की हरियाली बढ़ा रहे सौ से ज्यादा देववन

नेटवर्क
■ ओमप्रकाश सती

देहरादून। उत्तराखंड में जंगल बचाने का अनूठा अभियान रंग लाने लगा है। वनों को बचाने के लिए सौ से ज्यादा जंगल देवी देवताओं को चढ़ा दिए गए हैं। देववन बन जाने के बाद इनमें लोग लकड़ी काटने नहीं जाते। कई जगह भी नहीं चराते।

लोगों को डर रहता है कि देवता को चढ़ा दिए जंगल से पेड़-पौधे काटने पर देवी देवता नाराज हो जाएंगे। इससे ये जंगल खूब फल फूल रहे हैं। इनमें वनस्पतियों और जीव जंतुओं की कई प्रजातियां भी पनप रही हैं। ऐसे में ये जंगल हिमालयी क्षेत्र में जैव विविधता का उदाहरण बन रहे हैं। वन विभाग ऐसे जंगलों को पता लगाकर इनकी जीआईएस मैपिंग करेगा। साथ ही जैव विविधता पर शोध भी करेगा।

जानवरों का प्रवेश भी वर्जित

जंगलों को बचाने के लिए जानवरों का प्रवेश भी इनमें वर्जित होता है। कहा जाता है कि अगर जानवर जंगल में गए तो जंगल अपवित्र हो जाएंगे और जिससे देवी देवता नाराज हो सकते हैं। जंगलों में कूड़ा-कचरा भी नहीं फेंकते।

चार जिलों में ज्यादा संख्या

संजीव चतुर्वेदी के अनुसार उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ऐसे वन के सौ से ज्यादा होने का अनुमान है। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, पौड़ी आदि जिले हैं।

वन विभाग की अनुसंधान शाखा इन जंगलों पर इसी माह से शोध शुरू करने जा रही है। अनुसंधान शाखा के मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तराखंड में कई ऐसे जंगल हैं जो कि देवी देवताओं या मंदिरों के नाम से जाने जाते हैं। जिनको कि वन विभाग की भाषा में पवित्र वन भी कहा जाता है। इनमें ये डर दिखाया जाता है कि जो लोग इनको नुकसान पहुंचाएंगे वे देवी देवताओं को रुष्ट करेंगे। वन विभाग के पास ऐसे जंगलों का डाटा नहीं है कि ये कितने हैं, कहां-कहां हैं। डाटा बेस तैयार करने के लिए इसी माह शोध किया जाएगा।